



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 53 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 53]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

सं. टीएमपी/111/2000-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन शुल्क प्राधिकरण एकदम्भारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास में कंटेनर भंडारण प्रभारों के निर्धारण के संबंध में चेन्नई स्टीमर एजेंट संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनूसूची

मामला सं. 111/2000-सीएचपीटी

चेन्नई स्टीमर एजेंट संघ

..... आवेदक

बनाम

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

..... ..... प्रत्यर्थी

आदेश  
(14 फरवरी 2001 को पारित)

633

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में कंटेनर भंडारण प्रभारों के निर्धारण के सबध में चेन्नई स्टीमर एजेंट संघ (सीएसएए) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के सबध में है।

(i) सीएचपीटी ने जुलाई 1994 मे कंटेनर भंडारण प्रभारो मे काफी वृद्धि कर दी थी । सीएसएए ने मद्रास उच्च न्यायालय मे एक याचिका दाखिल कर दी और 11 जुलाई 94 को स्थगन ले लिया ।

(ii) सीएचपीटी ने 1995 मे एक उपसमिति का गठन किया और अमरीकी डॉलर मे निधारित दरो को संशोधित किया । भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई 1995 को इसे 6 जुलाई 1994 से पूर्व प्रभाव से अनुमोदित कर दिया गया । कुछ स्लैबो की दरे अभी भी अधिक थीं और कुछ और तत्व लागू कर दिए गए थे । अतः अप्रैल 1997 मे एक और रिट याचिका दाखिल कर दी गई और स्थगन को बढ़ा दिया गया ।

(iii) इसी दौरान महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने सीएचपीटी की दरो मे सामान्य संशोधन किया और 22 मार्च 2000 को आदेश पारित कर दिया । परंतु इस मद को न्यायाधीन होने के कारण शामिल नहीं किया गया ।

(iv) फरवरी / अगस्त 2000 मे दो रिट याचिकाएं अंतिम सुनवाई के लिए आई और माननीय उच्च न्यायालय ने दो पत्तन न्यास अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया ।

(v) यह ज्ञात होने पर कि सीएचपीटी निर्णय के खिलाफ अपील करने जा रही है, सीएसएए ने सीएचपीटी से अपील वापस लेने और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से पहले न किए गए कंटेनर भंडारण प्रभारों को संशोधित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ।

(vi) सीएचपीटी ने चूंकि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की अतः सीएसएए ने महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से हस्तक्षेप करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इस प्रकार की कार्रवाई दोनों पक्षकारों के सर्वोत्तम हित मे होगी और इससे समय तथा कानूनी खर्चों की बचत होगी ।

3.1 सीएसएए का अभ्यावेदन सीएचपीटी को और विभिन्न प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधिक संस्थाओं को उनके अभिमत जानने के लिए अग्रेषित कर दिया गया । उनसे प्राप्त अभिमतों का सार इस प्रकार है -

### कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (सीएसएलए)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता सर्वाधिक सहायक होगी क्योंकि लबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया पत्तन, स्टीमर एजेट एसोसिएशन और आखिरकार व्यापार के लिए हानिकर होगी । अत महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को मामले मे हस्तक्षेप करना चाहिए और वाणिज्यिक समझौता करवाना चाहिए ।

### मद्रास वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर (एमसीसीआई)

- (i) सोएसएए द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मे विधिसम्मत तर्क दिए गए है और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को हस्तक्षेप करके कंटेनर भडारण दरो के बारे मे निर्णय करना चाहिए ।
- (ii) सीएचपीटी ने 1994 मे जिस समय इन विवादास्पद कंटेनर भडारण प्रभारो की घोषणा की थी उस समय महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अस्तित्व मे नहीं था ।
- (iii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मामला न्यायाधीन होने के कारण मार्च, 2000 मे पारित आदेश के अनुसार पत्तन प्रशुल्क सशोधन के सप्तक (गैमट) मे कंटेनर भडारण प्रभार शामिल करने मे असमर्थ था परन्तु 28 अगस्त 2000 को निर्णय की घोषणा किए जाने के बाद मामला न्यायाधीन नहीं रहा था । तब सीएचपीटी को मामला अतिम निर्णय हेतु महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए था । 1994 मे वसूल की गई दरो के सबध मे विवादो को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रद्द किया जा सकता है ।

(iv) इस निर्णय के विरुद्ध अपील पर सीधे कार्यवाही करके, सीएचपीटी ने महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की भारत सरकार द्वारा विशेषकर पत्तन प्रशुल्क के लिए स्थापित की गई सेवाओं का प्रयोग करना तो छोड़ दिया है और न्यायालय का समय बर्बाद करने में लगा हुआ है।

(v) वर्ष 1994 वाली स्थिति अब बदल चुकी है। इस समय 11 ऑफ डॉक सीएफएस सक्रिय हैं जो आयातकों को अपने एफसीएल कंटेनर पत्तन परिसरों से दूर रखने का पूरा अवसर देते हैं, इससे पत्तन न्यास के परिसरों में भीड़ कम होती है। अतः पत्तन न्यास के परिसरों पर भीड़-भाड़ होने का कोई मौका नहीं आता और इससे पत्तन न्यास का यह तर्क विफल हो जाता है कि असाधारण रूप से उनकी अत्यधिक भंडारण दरों ने परेषितियों को पत्तन न्यास परिसरों के भीतर अपने बॉक्स को छोड़ने के लिए हतोत्साहित करने का कार्य किया। विधिक कार्यवाही करना अनुचित है क्योंकि 1994 के बाद घटनाओं के नया मोड़ लेने से विवादास्पद मुद्दा अव्यावहारिक हो गया है।

### हिंदुस्तान वाणिज्य चैम्बर (एचसीसी)

(i) पत्तन न्यास द्वारा कंटेनरों में आयातित कार्गो पर दो प्रकार की लेवी वसूल की जाती है : प्रति मी.ट. आधार पर कार्गो पर वसूल किए जाने वाले विलंब शुल्क प्रभार जिसकी वसूली परेषिती से की जाती है और कंटेनर भंडारण प्रभार जिसकी वसूली शिपिंग लाइनों से की जाती है। शिपिंग लाइनें इसके लिए परेषितियों से उस समय भंडार प्रभार वसूल करती हैं जब वे सुपुर्दगी आदेश के लिए उनसे संपर्क करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वसूलियाँ आयातकों को ही भरनी पड़ती हैं। शिपिंग लाइनों का पत्तन न्यास के साथ खाता चलता रहता है और भंडारण प्रभार नियमित रूप से उनके खातों में डेबिट कर दिए जाते हैं और यहाँ तक कि छोड़ दिए गए कंटेनरों के लिए भी प्रभार डेबिट कर दिए जाते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है।

(ii) सीएचपीटी को आयातित एफसीएल कंटेनरों पर विराम अवधि बढ़ने की समर्या का सामना करना पड़ रहा था और इससे कंटेनर टर्मिनल पर भीड़ भी हो जाया करती थी अतः सीएचपीटी ने इस भीड़ को कम करने के लिए 1994 में कंटेनर भंडारण प्रभारों में वृद्धि कर दी। परंतु यह वृद्धि बहुत अधिक थी।

(iii) 6 जुलाई 94 से पहले स्टीमर एजेंट कंटेनर भंडारण प्रभारों का वहन कर लिया करते थे परंतु सीएचपीटी द्वारा दरों में असाधारण वृद्धि कर दिए जाने से स्टीमर एजेंटों ने परेषितियों से भंडारण प्रभारों की वसूली करनी शुरू कर दी। इस प्रकार वास्तविकता तो यह है कि स्टीमर एजेंट यह लड़ाई परेषितियों के हित में लड़ रहे हैं और स्वयं को उस बड़े भारी नुकसान की संभावना से सुरक्षित कर रहे हैं जो उन्हे परेषण छोड़ दिए जाने की स्थिति में उठाना पड़ेगा।

(iv) सीएचपीटी को रटीमर एजेट संघ को विचार-विमर्श के लिए बुलाना चाहिए और बातचीत करके सोहार्दपूर्वक इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए तथा कंटेनर भंडारण प्रभारों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 95 के आदेश में अधिसूचित दरों को 1 अप्रैल 98 से लागू करना चाहिए और बाहर ही रोक देने, अतिरिक्त संचलन तथा निष्कासन के प्रभारों को 1 अप्रैल 2000 से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

(v) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण नई दरें विचार करके अधिसूचित कर सकता है अर्थात् एफसीएल कटेनरों के लिए कंटेनर भंडारण प्रभार समाप्त कर दिए जाए और 15 दिन के बाद 10 निःशुल्क दिन छोड़ने की अनुमति देकर विलंब शुल्क प्रभार बढ़ा दिए जाएं ।

### दक्षिण भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर (एसआईसीसीआई)

विवादास्पद कंटेनर प्रभारों की घोषणा चेन्नई पत्तन न्यास ने 94 में उस समय की थी जब महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना भी नहीं हुई थी । अब चूंकि प्राधिकरण अस्तित्व में आ चुका है और प्राधिकरण की उपशोगी भूमिका को ध्यान में रखकर यह बेहतर होगा कि प्राधिकरण इस मामले में मध्यस्थिता करे और सबके हित में एकबार ही इस मामले का समाधान करे । इससे इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों का समय भी बचेगा ।

### भारतीय राष्ट्रीय पोतवणिक संघ (आईएनएसए)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी संबंधित पक्षकारों से संबंधित आकड़े मंगवाकर उन पर पर्याप्त विचार करने निर्णय लेना चाहिए ।

### भारतीय जहाज़रानी निगम (एससीआई)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को सीएसए द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का स्वीकार करना चाहिए ।

3.2 सीएसए ने अपने 12 दिसंबर 2000 के पत्र द्वारा श्री सी.ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिकारी, चेन्नई की विधिक राय की प्रति भेजी है । इसमें उन्होंने यह राय दी है कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के आदेश को चेन्नई में कार्यरत सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित ऑफ-जॉक रीएफएस पर लागू किया जा सकता है और प्राधिकरण को रिट अपीलों के लंबित रहने के दौरान कंटेनर भञ्जारण प्रभारों को पुनः निर्धारित करने और कंटेनरों पर भंडारण प्रभारों की वसूली को भी 75 दिन की अवधि तक प्रतिबंधित करने का प्राधिकार है ।

4. सीएचपीटी ने अपने 27 दिसंबर 2000 के पत्र द्वारा अपने अभिमत प्रस्तुत किए हैं। सीएचपीटी ने बताया है कि कंटेनर भंडारण प्रभारों के संबंध में सीएचपीटी ने विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय को प्रभावी करने के विरोध में स्थगन आदेश ले लिया है और माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी (सीएसएए) को 19 जुलाई 95 के संशोधन प्रशुल्क के अनुसार 22 नवंबर 2000 के कंटेनर भंडारण प्रभारों का भुगतान करने का आदेश दिया है। सीएचपीटी ने कहा है कि इस मामले में अंतिम कार्रवाई सीएचपीटी द्वारा दाखिल की गई अपील का निर्णय होने के बाद ही की जा सकती है। सीएचपीटी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह मामले के न्यायाधीन होने के कारण इस कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दे।

5.1 सीएचपीटी के उपर्युक्त पत्र की प्रति सीएसएए को और अन्य विभिन्न प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधिक संस्थाओं को उनका यह विशेष अभिमत जानने के लिए प्रेषित कर दी गई है कि सीएचपीटी के अनुरोध को क्यों न स्वीकार किया जाए।

5.2 सीएचपीटी के विचारों के संबंध में एचसीसी, सीएसएए और एससीआई ने अपने अभिमत भेजे हैं जिनका सार इस प्रकार है :-

### हिंदुस्तान वाणिज्य चैम्बर (एचसीसी)

सीएचपीटी को जिस निर्णय के विरुद्ध अपील करनी पड़ी उसमें भी पत्तन को यह निर्देश दिया गया था कि उन्हें सीएसएए के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए अतः महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मध्यस्थ का काम कर सकता है और इस मामले में संयुक्त बैठक में पत्तन और स्टीमर एजेंटों के विचारों पर चर्चा करके आम सहमति बनाई जा सकती है। प्राधिकरण का निर्णय अंतिम निपटान हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि न्यायालय को इस व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं होगी। पत्तन यदि मामले का समाधान नहीं होता है तो उसके कारण लंबे समय तक चलने वाले मुकदमें से भी मुक्ति पा सकेगा।

### चेन्नई स्टीमर एजेंट एसोसिएशन (सीएसएए)

- (i) अप्रैल 2000 में जब सीएचपीटी की दरों के मान में सामान्य संशोधन किया गया था उस समय प्राधिकरण ने इस विशेष मद "कंटेनर भंडारण प्रभार" को न्यायाधीन होने से शामिल नहीं किया था।
- (ii) रिट याचिका 1994 की 11746 और 1997 की 5806 में लिए गए निर्णय की घोषणा 28 अगस्त 2000 को की गई थी और सीएचपीटी को यह फैसला करने के लिए एक माह का समय मिला था कि मुकदमे को और आगे चलाया जाए या मामले को सामान्य संशोधन के समय छोड़ दी गई मदों को संशोधित करने के लिए प्राधिकरण के पास भेज दिया जाए। परंतु सीएचपीटी ने रिट अपील दाखिल कर दीं

जिस पर कार्रवाई करना बड़ा ही टेढ़ा काम है। ऐसे समय में सीएसए ने अध्यक्ष, (सीएचपीटी) से व्यक्तिगत रूप से लिखकर अपील की कि कंटेनर भड़ारण प्रभारों से संबंधित इस मामले में यथाशीघ्र समाधान करने के लिए यह मामला महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को भेज दिया जाए।

- (iii) जब पत्तन प्रशुल्क (दरों के मान) में संशोधन करने के लिए वैकल्पिक संस्था बनाई गई है तो सीएचपीटी को मुकदमा जारी रखने के बजाय प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।
- (iv) प्रयोक्ता संस्थाओं जैसे एचसीसी, आईएनएसए और थेन्नई कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन ने जिनके सीएचपीटी बोर्ड में नामिती हैं, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को पहले ही लिखा है कि वह मुकदमे को समाप्त करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे। एमसीसीआई और सीएसएलए ने भी इसी प्रकार के अनुरोध किए हैं।

### भारतीय जहाज़रानी निगम (एससीआई)

- (i) सीएचपीटी का यह विवाद कि मामला न्यायाधीन है और इसीलिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पूरी तरह भ्रामक है और व्यापार के हित में नहीं है। सीएसए ने अपने 9 जनवरी 2001 के पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से कारण पूछा है कि उनका अनुरोध क्यों न स्वीकार किया जाए। संशोधित भंडारण प्रभार का मामला जहाँ तक संभावित मामलों का संबंध है अब न्यायाधीन नहीं है।
- (ii) हाल में सीएचपीटी ने कंटेनर बिलों को इस शर्त पर पास करना शुरू कर दिया है कि पूर्व संशोधित और संशोधित दरों के बीच प्रभार की राशि में यदि कोई अंतर होगा तो उसकी वसूली पृथक से की जाएगी। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब मामला न्यायाधीन नहीं है क्योंकि न्यायालय ने अपने 22 नवंबर 2000 के आदेश द्वारा इसका यह कहकर निपटान कर दिया है कि संशोधित प्रशुल्क के दरों पर कंटेनर भंडारण प्रभारों का भुगतान 22 नवंबर 2000 से करना होगा। अब केवल 6 जुलाई 94 से 21 नवंबर 2000 के अवधि के लिए संशोधित प्रशुल्क लागू किए जाने के बारे में ही न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है।
- (iii) न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया संशोधित प्रशुल्क ही नहीं है बल्कि सभी भारतीय पत्तनों की तुलना में काफी अधिक है जिससे निश्चित ही इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। अतः महसूस किया गया है कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बारे में सभी के विचार जानने चाहिए। इससे प्राधिकरण को इस व्यापार पर थोपे गए प्रशुल्कों के औचित्य को निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

6. सीएसएए ने अपने 4 जनवरी 2001 के पत्र द्वारा एक और अभ्यावेदन संयुक्त सुनवाई में विचार किए जाने के लिए भेजा है। सीएसएए ने मामले की शुरूआत तथा क्रमवार उसका पूरा विवरण, मुख्य भारतीय पत्तनों में भंडारण प्रभारों की तुलना, मुख्य भारतीय पत्तनों में नि शुल्क दिनों की तुलना और विचारणीय कुछ मुद्दों से संबंधित विवरण संलग्न किए हैं। मुख्य तथ्य इस प्रकार है :-

- (i) सीएचपीटी द्वारा अधिसूचित प्रभार पहले ही मनमाने और बहुत अधिक हैं और अन्य भारतीय पत्तन में दी जा रही सुविधाओं तथा प्रशुल्कों से उनका कोई मेल नहीं है।
- (ii) इस मामले के समाधान के लिए लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से सीएचपीटी और सीएसएए दोनों के समय और संसाधनों की बर्बादी होगी।
- (iii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण महापत्तन न्यासों में प्रशुल्क संबंधी मामलों पर निर्णय करने हेतु भारत सरकार का अधिकार प्राप्त साविधिक निकाय है।
- (iv) सीएसएए प्राधिकरण से लंबे समय से लंबित इस मामले में हस्तक्षेप करने और निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध करता है।
  - (क) सीएचपीटी में प्रयोक्ताओं को दिए जाने वाले बहुत ही सीमित निःशुल्क समय पर पर्याप्त विचार करते हुए भविष्य में चेन्नई पत्तन में भी अन्य मुख्य पत्तनों में प्रचलित प्रशुल्कों के अनुसार ही भंडारण प्रभार अधिसूचित करने।
  - (ख) जून 1994 में प्रचलित भंडारण प्रशुल्कों को जुलाई 1994 से लेकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नये प्रशुल्क के लागू होने की तारीख तक की पूरी अवधि में औपचारिक रूप से लागू करने।

7. इस मामले में 25 जनवरी 2001 को चेन्नई में सीएचपीटी के परिसर में संयुक्त सुनवाई की गई। संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किए गए -

#### चेन्नई स्टीमर एजेंट एसोसिएशन (सीएसएए)

- (i) न्यायालय ने प्राधिकरण को भविष्य में इस मामले की जाँच करने से नहीं रोका है।
- (ii) सीएचपीटी का कहना है कि यह निवारक निर्णय है। क्या यह व्यापार द्वारा भीड़भाड़ या कंटेनरों का आयात करने लाने वाली लाइनों के विरुद्ध है?
- (iii) इस समय काफी ऑफ - डॉक सीएफएस है।

- (iv) पत्तन न केवल कंटेनर प्राप्त करने बल्कि यथोचित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी पूरी तरह आबद्ध हैं।
- (v) दरें असाधारण रूप से अधिक हैं।
- (vi) जब 1995 में यह दर अधिसूचित की गई थी उस समय प्राधिकरण अस्तित्व में ही नहीं था। यही कारण है कि अब हम प्राधिकरण रो दरों पर पुनर्विचार करने और उनके संशोधन करने की अपेक्षा करते हैं।
- (vii) सामान्य संशोधन में इस प्रशुल्क को न्यायाधीन होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। अब वूँकि न्यायालय ने भविष्य में विचारार्थ इसकी मंजूरी दे दी है अतः सीएचपीटी को प्राधिकरण के पास जाना चाहिए।

#### भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई)

पत्तन ने भविष्य में दरों को लागू करने के विनिर्णय को स्वीकार कर लिया है। इससे पता चलता है कि वे पूरे मामले पर विचार करना चाहते हैं। फिर यह न्यायाधीन कहाँ रहा?

#### चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

- (i) सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से दरों को लागू करने का आदेश दिया गया था।
- (ii) पूरा मामला अभी भी न्यायालय में है।
- (iii) न्यायालय ने दरों के औचित्य को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है।
- (iv) केवल 'प्रभावी होने की तारीख' के बारे में निर्णय लिया जाना है। सीएचपीटी जुलाई 95 की तारीख निर्धारित करना चाहता है। इसके लिए समझौता किया जा सकता है।
- (v) यदि हम अब दरें कम कर देते हैं तो इसमें लेखा परीक्षा आपत्ति होगी। इसके अलावा इससे हमारा मामला न्यायालय में और भी कमज़ोर पड़ जाएगी।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में और संयुक्त सुनवाई में दिए गए तर्कों पर विचार करने पर निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i) प्राधिकरण के मार्च 2000 में पारित आदेश के अनुसार दरों के मान में सामान्य संशोधन करने के समय इस दर को पुनर्विचार/संशोधन के लिए स्वीकार नहीं किया

गया क्योंकि उस समय यह मामला मद्रास उच्च न्यायाल की एक न्यायाधीश की पीठ के समक्ष विचाराधीन था ।

- (ii) मामले का अब एक न्यायाधीश की पीठ द्वारा निपटान कर दिया गया है । मामले में निर्णय याचिकाकर्ताओं अर्थात् सीएसए ए के पक्ष में दिया गया था ।
- (iii) सीएचपीटी ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील कर दी । न्यायालय ने उस प्रतिकूल आदेश के प्रभावी होने के विरुद्ध स्थगन आदेश दे दिया जिसमें संशोधित दरों की वसूली भावी प्रभाव से 22 नवंबर 2000 से करने की अनुमति दी गई थी ।
- (iv) न्यायालय ने प्राधिकरण पर इस मामले में भावी विचार करने पर कोई रोक नहीं लगाई है । सीएसए ने प्राधिकरण से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते समय इस बात को रेखांकित किया । उन्होंने अपने काउंसेल द्वारा दी गई राय की एक प्रति भी इस आशय से भेजी है कि अपील के खंडपीठ के समक्ष लंबित होने के बावजूद प्राधिकरण इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है ।

हालांकि इस विधिक मामले पर दो प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं परंतु हस्तक्षेप न करने में ही अधिक सुविधा होगी । इस परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह मामला वास्तव में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आदेश है । भावी परिप्रेक्ष्य में भी प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विश्लेषण को या उसके किसी भी आदेश लो प्रतिकूल आदेश के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के सदृश माना जाएगा । और ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो यह प्राधिकरण के लिए कदापि उचित नहीं होगा ।

- (v) सीएचपीटी द्वारा खंडपीठ के समक्ष अपील करने की कार्रवाई को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि प्रतिकूल आदेश को प्राधिकरण के मंच पर चुनौती दी जा सके ।

संयोग से प्रतिकूल आदेश में यह मत भी व्यक्त किया गया है कि प्रशुल्कों का पूर्व प्रभाव से निर्धारण नहीं किया जा सकता । परंतु विधि मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण को विशेष परिस्थितियों में प्रशुल्क दरों पूर्व प्रभाव से अधिसूचित करने का भी अधिकार है । ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि इस मामले में भी निर्णय समुचित अपील प्राधिकारी ही करे ।

यदि प्राधिकरण के मंच पर ऐसी कोई समानांतर कार्यवाही सीएचपीटी द्वारा दाखिल अपील के गुणावगुणों (मेरिट) पर प्रतिकूल प्रभावी डाले बिना की जानी हो तो ऐसी

कार्यवाही संबंधित खंडपीठ के इस आशय के निदेशों के अनुसरण में ही की जा सकती है। अन्यथा उपर्युक्त पैराग्राफ (iv) में उद्धृत संवेदनशीलता/ सुग्राहिता के कारण प्राधिकरण के लिए हस्तक्षेप करने में बाधा खड़ी हो जाएगी।

अतः याचिकाकर्ताओं को स्पष्टतया सुझाव दिया जाता है कि वे इस प्रकार के निदेश के लिए संबंधित खंडपीठ से संपर्क करें।

(vi) संभवतः यह तर्क दिया जा सकता है कि सीएचपीटी को इस मामले में प्रशुल्क के भावी निर्धारण हेतु प्राधिकरण से संपर्क करने में कोई बाधा नहीं आएगी। परंतु जैसा कि सीएचपीटी ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति का निर्धारण करने में वास्तव में दो प्रकार की समस्याएं आएंगी :-

- (क) अपने निर्णय में एकाएक परिवर्तन करने से लेखा परीक्षा आपत्ति हो सकती है।
- (ख) पूर्व प्रभाव से कम दर स्वीकार करने के कारण पीठ के समक्ष अपील का मामला कमज़ोर पड़ सकता है।

(vii) सीएसएए और अन्य प्रयोक्ताओं ने यह तर्क दिए हैं कि सीएचपीटी अब ऑफ-डॉक सीएफएस आदि काफी होने से न केवल कंटेनर प्राप्त करने बल्कि समुचित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी जिम्मेदार है। उपर्युक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण के लिए इस स्तर पर इस मामले के गुणावगुणों (मेरिट) की जाँच करना आवश्यक नहीं है।

(viii) कुछ प्रयोक्ता संस्थाओं ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकरण विकल्प के तौर पर इस मामले में मध्यस्थिता कर सकता है। परंतु यह संभव नहीं है कि मध्यस्थिता से दोनों ही पक्षकार सहमत हों और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह प्राधिकरण अधिनिर्णयिक निकाय है, माध्यस्थ निकाय नहीं।

9. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, प्राधिकरण निर्णय लेता है कि इस मामले में इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उसके लिए विधिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतः चेन्नई स्टीमर एजेंट एसोसिएशन के अभ्यावेदन को खारिज किया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2000/असा.]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2001

**No. TAMP/111/2000-CHPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation submitted by the Chennai Steamer Agents' Association relating to fixation of container storage charges at the Chennai Port Trust, as in the Order appended hereto.

## SCHEDULE

Case No.TAMP/111/2000-CHPT

The Chennai Steamer Agents' Association	---	Applicant
---	-----	-----------

Vs

The Chennai Port Trust (CHPT)	---	Respondent
-------------------------------	-----	------------

**ORDER**

(Passed on this 14th day of February 2001)

This case relates to a representation submitted by the Chennai Steamer Agents' Association (CSAA) relating to fixation of container storage charges at the Chennai Port Trust (CHPT).

2. In its representation, the CSAA has given the following points:

- (i). In July 1994, container storage charges were considerably enhanced by the CHPT. The CSAA filed a petition in the High Court of Madras and stay was obtained on 11 July 94.
- (ii). The CHPT, set up a Sub-Committee in 1995 and revised the rates denominated in US \$. This was approved by the Ministry of Surface Transport on 19 July 1995 retrospectively with effect from 6 July 1994. As the rates for certain slabs were still on the high side and some new elements were introduced, the another writ petition (WP No.5806 of 1997) was filed in April 1997 and stay was extended.
- (iii). In the meanwhile, the TAMP undertook a general revision of the CHPT and an Order passed on 22 March 2000. However, this item was excluded as it was subjudice.
- (iv). The two Writ Petitions came up for final hearing in February/August 2000 and the Hon'ble High Court struck down the two Port Trust Notifications and allowed the Writ Petitions.
- (v). After learning that the CHPT was going in Appeal against the judgment, the CSAA requested the CHPT to withdraw the Appeal and seek the Intervention of TAMP to revise the Container Storage Charges which could not be done earlier.
- (vi). As there was no response from the CHPT, the CSAA has approached the TAMP to intervene and do the needful as it felt that such a course of action would be in the best interests of both parties saving on time and legal expenses.

3.1. The representation of the CSAA was forwarded to the CHPT and various users/representative bodies of users for their comments. Comments received from them are summarised below:

**The Container Shipping Lines Association (CSLA)**

The arbitration by the TAMP should be most helpful as otherwise a protracted legal process will ensue to the detriment of the Port, the Steamer Agents' Association and ultimately to the trade. Therefore, the TAMP should intervene in the matter and secure a commercial settlement.

**Madras Chamber of Commerce and Industry (MCCI)**

- (i). The representation made by the CSAA has valid arguments and the TAMP must intervene and adjudicate on the container storage rates.
- (ii). The TAMP was not in existence when these disputed container storage charges were promulgated by the CHPT in 1994.
- (iii). The TAMP was unable to include container service charges in the gamut of Port tariff revision ordered in March 2000, as the matter was subjudice, but after pronouncement of judgment on 28 August 2000, the matter was no longer subjudice. The CHPT should then have to use this opportunity to bring up the matter to TAMP for a final decision. As to the dispute regarding the rates levied in 1994, these can be struck down as per the judgment of the High Court.
- (iv). By directly proceeding to appeal against this judgment, the CHPT has excluded utilising the services of TAMP which was specially set up by the Government of India for Port tariff and instead continues to waste the Court's time.
- (v). The situation prevailing in 1994 has since been changed. As many as 11 off Dock CFSs are now active which give ample opportunity for the importers to have their FCL containers moved away from the Port premises, resulting in less congestion at the Port Trust premises. Therefore, there is little chance for the port trust premises being congested and in turn this defeats the argument of the Port Trust that their extraordinarily high storage rates were to act as an disincentive for consignees to leave their boxes inside the port trust premises. Legal recourse is unwarranted since the issue at dispute have been rendered almost academic by the turn of events subsequent to 1994.

**The Hindustan Chamber of Commerce (HCC)**

- (i) The two levies collected by the Port Trust on cargo imported in containers are demurrage charges levied on the cargo on a per MT basis which is collected from the consignee and the container storage charges which is collected from the shipping lines. The shipping lines in turn collect the storage charges f.o.r. the consignee when approached for delivery order. Hence, both the levies are borne by importers only. As the Shipping Lines have running accounts w/i the Port Trust, the storage charges are debited to this account on a regular basis and even for containers that are abandoned which is a loss to them.
- (ii). The CHPT had been facing the problem of increasing dwell time on imported FCL containers and this was also resulting in congestion at the Container Terminal. In order to reduce the congestion the CHPT increased the container storage charges in 1994. The increase was, however, very steep.
- (iii). Prior to 6 July 94, the Steamer Agents used to absorb the container storage charges. However, after the rates were increased abnormally by the CHPT, the Steamer Agents have started collecting storage charges from the consignees. Hence, in actual, the Steamer Agents are fighting this in the interest of the consignees and protecting themselves from the prospect of losing large sums of money when the consignment is abandoned.
- (iv) The CHPT should call the Steamer Agents Association for a discussion and amicably settle the issue with negotiating and fixing the rate notified by the GOI in the order dated 17 September 95 with effect from 1 April 98 with regard to the Container Storage Charges and for the Shut out, extra Movement, and removal charges may be implemented from 1 April 2000.

(v). The TAMP can consider and notify new rates, i.e., the container storage charges for FCL containers be deleted and the demurrage charges be increased after 15 days after permitting the 10 free days allowed today.

**The Southern India Chamber of Commerce and Industry (SICCI)**

The disputed container storage charges were promulgated by the Chennai Port Trust way back 94 when the TAMP was not established. Since the TAMP has now come into existence and in view of the useful role played by the TAMP it will be better if the TAMP can arbitrate in the matter and settle the issue once for all. This will also save considerable time to all parties concerned with the issue.

**The Indian National Shipowners' Association (INSA)**

The TAMP should intervene and call for all relevant data from all parties concerned and give its considered decision.

**The Shipping Corporation of India (SCI)**

The TAMP may take up the representation made by the CSAA.

3.2. The CSAA vide its letter dated 12 December 2000 has forwarded a copy of the legal opinion of Shri. C.A. Sundaram, Sr. Advocate, Chennai who opined that the TAMP's Order can be extended to Customs notified Off-Dock CFSs operating in Chennai and the TAMP has the authority to refix the container storage charges during the pendency of WAs and also limit levy of storage charges on containers to a period of 75 days.

4. The CHPT vide its letter dated 27 December 2000 has submitted its comments. The CHPT has stated that in respect of container storage charges, CHPT has obtained stay against operation of the judgment by learned single judge and the Division Bench of the Hon'ble High Court has ordered for payment of container storage charges as per revised tariff of 19 July 95 from 22 November 2000 by the Respondent (CSAA). The CHPT has mentioned that final action in the matter can be taken only after the outcome of appeal filed by CHPT. The CHPT has requested the Authority to defer this proceeding, since the matter is subjudice.

5.1. A copy of the above letter of the CHPT has been forwarded to the CSAA and also to other various users / representative body of users for their specific comments on why the request of the CHPT shall not be accepted.

5.2. The HCC, CSAA and SCI have sent their comments on the views of the CHPT, which are summarised below:

**The Hindustan Chamber of Commerce (HCC)**

The judgment against which the CHPT has gone on appeal also had directed the Port that they should hold discussion with the CSAA. Hence, TAMP can act as an arbitrator and decide the issue by holding joint meeting wherein the views of the port and the Steamer agents can be discussed and a consensus can be arrived at. The decision of TAMP can be filed with the Court for final disposal as the court will have no objection to this arrangement. The port will also be able to find a way out from the long drawn litigation that may follow if the issue is not settled.

**The Chennai Steamer Agents' Association (CSAA)**

(i). When there was a general revision of the CHPT Scale of Rates in April 2000, this particular item 'container storage charges' was excluded by the TAMP as it was subjudice.

- (ii) The judgment in the WPs Nos. 11747 of 1994 and 5806 of 1997 was pronounced on 28 August 2000 and the CHPT had one month time to decide whether to prolong the litigation or to refer the matter to TAMP to revise the rates which had to be omitted during the general revision. Instead, the CHPT have filed Writ Appeals which action is cantankerous. At this juncture the CSAA wrote to the Chairman, (CHPT) and personally appealed to him to refer this matter to TAMP for a speedy and early resolution of the issue relating to container storage charges.
- (iii). When there is an alternate body specifically created to revise port tariff (Scale of Rates), the CHPT should have approached the TAMP instead of continuing the litigation.
- (iv). User Bodies like the HCCs, INSA and Chennai Custom House Agents Association who have a nominee on the CHPT Board have already written to TAMP seeking its intervention in the matter with a view to end the litigation. The MCCI and CSLA have also made a similar request.

#### The Shipping Corporation of India (SCI)

- (i). The contention of CHPT that the matter is subjudice and, as such, TAMP cannot intervene in the matter is totally misleading and not in the interest of the trade. The CSAA has very clearly set out the reason as to why the request should not be granted, vide their letter dated 9 January 2001. The matter, regarding the revised storage charge is no longer subjudice as far as the prospective cases are concerned
- (ii) Recently, CHPT has started qualifying the container bills with a condition that the difference in charges between the pre-revised and revised rates will be collected separately. It is, therefore, amply clear that the matter is no longer subjudice as it has been cleared by the court, vide their order dated 22 November 2000 stating that the trade will have to pay the container storage charges at the rates as per the revised tariff from 22 November 2000. The applicability of the revised tariff for the period from 6 July 94 to 21 November 2000 is only required to be decided by the court
- (iii). The revised tariff which has been cleared by the court is not only exorbitant but also the highest among all Indian ports which definitely requires to be reviewed again. It is, therefore, felt that the TAMP should intervene in the matter and the views of the trade should be heard which may help the TAMP to weigh the reasonability of the tariff which has been imposed upon the trade

6 The CSAA has sent another representation vide its letter dated 4 January 2001 for consideration at the joint hearing. The CSAA has enclosed genesis and chronology of the case, comparison of storage charges in main Indian ports, comparison in free days in main Indian ports and salient points to be considered. The main points are given below.

- (i). The CHPT notified charges are already arbitrary, exorbitant, and with no relationship to the service rendered or to the tariffs prevailing in other Indian Ports
- (ii). Prolonged litigation to resolve this issue is a drain on the time and resources of both CHPT and CSAA.
- (iii) TAMP is the Statutory body empowered by the Government of India to adjudicate on tariff matters in Major Port Trusts

- (iv). The CSAA prays for the intervention of TAMP in this long pending dispute and requests the action of TAMP in:
  - (a). Notifying storage charges in Chennai Port prospectively in line with the tariffs in other main ports, giving due cognisance to the very limited free time extended to users in CHPT.
  - (b). Formalising the application of the storage tariff prevailing in June 1994, through the period from July 1994 till the commencement date of the new tariff to be fixed by TAMP.

7. A joint hearing in this case was held on 25 January 2001 at the CHPT premises in Chennai. At the joint hearing the following submissions were made:

**The Chennai Steamer Agents' Association (CSAA)**

- (i). The Court has not restrained the TAMP from looking into the matter prospectively.
- (ii). CHPT says, it is a deterrent. Is it against congestion by Trade or against Lines bringing in containers?
- (iii). There are enough off-dock CFSs now.
- (iv). Port is duly bound not only to receive containers but also to provide for reasonable storage facilities.
- (v). Rates are abnormally high.
- (vi). When this rate was notified in 1995, TAMP did not exist. That is why we now want TAMP to review and revise the rates.
- (vii). In the general revision, this tariff was not covered on the sub judice consideration. Now that the Court has cleared a prospective consideration, the CHPT should go back to the TAMP

**The Shipping Corporation of India (SCI)**

Port has accepted the ruling about prospective application. That shows they are willing to discuss the whole matter. Where is sub judice?

**The Chennai Port Trust (CHPT)**

- (i). Retrospective application was ordered by the Government.
- (ii). The whole matter is still in the court
- (iii). The court has implicitly accepted the reasonableness of the rate
- (iv). Only the 'date of effect' remains to be settled. The CHPT is willing to fix the date as July 95. There can be a settlement
- (v). If we reduce the rate today, there will be audit objection. Further, it can also weaken our case in the court.

8. With reference to the totality of information collected during the proceedings of this case, and taking into account the arguments advanced at the joint hearing, the following position emerges:

- (i). This rate was not taken up for review/revision at the time of the general revision of the Scale of Rates ordered by this Authority in March 2000 as the matter was then pending before a Single Judge Bench of the Madras High Court.
- (ii). The case has since been disposed of by the Single Judge Bench. The case was decided in favour of the Petitioners viz., the CSAA.
- (iii). The CHPT has gone up in appeal to a Division Bench of the Madras High Court which has stayed operation of the impugned Order while permitting levy of the revised rates prospectively with effect from 22 November 2000.
- (iv). The Court has not restrained this Authority from taking up this case for prospective consideration. This fact has been highlighted by the CSAA to urge this Authority to intervene in the matter. They have also sent a copy of an opinion given by their Counsel to the effect that, notwithstanding the pendency of the appeal before the Division Bench, this Authority can intervene in the matter.

While this legal issue can be argued both ways, the balance of convenience would seem to lie in favour of non-interference. It has, in this context, to be recognised that what is in reference, in fact, is an order of a Judge of the High Court. Any analysis by and any order of this Authority even on a prospective perspective can be seen to amount to expression of opinions about the impugned order. And, it will not at all be appropriate for this Authority to be seen in that position.

- (v). The action taken by the CHPT to go up in appeal to a Division Bench cannot be faulted. There is no way in which the impugned order could have been challenged in the forum of this Authority.

Incidentally, there is also an observation in the impugned order that there could be no retrospective prescription of tariffs. But, according to the Ministry of Law, this Authority has the power in special circumstances to notify tariff rates with retrospective effect also. In the event, it is best that a proper Appellate Authority decides on this issue also.

If there is to be any parallel proceedings in the forum of this Authority without prejudice to the merits of the appeal filed by the CHPT, it can best be so only in pursuance of a directive to that effect from the Division Bench concerned. Otherwise, the vulnerability/sensitivity cited in paragraph (iv) above will still loom as a hurdle for this Authority to intervene.

The Petitioners will, therefore, be well advised to approach the Division Bench concerned for such a directive.

- (vi). It can possibly be argued that there will be no legal hurdle to the CHPT approaching this Authority for a prospective prescription of the tariff in this case. But, as has been contended by the CHPT, it will have two real difficulties to reckon with in such a contingency:
  - (a). There can be an audit objection about the sudden reversal of its stand.
  - (b). Any acceptance of a lower rate (even) prospectively can have a repercussion of weakening its appeal case before the Division Bench.

- (vii). The CSAA and other users have advanced arguments about the CHPT being duty bound not only to receive containers but also to provide for reasonable storage facilities, there being enough off-dock CFSs now, etc. In the backdrop of the legal position described above, it is not necessary for this Authority at this stage to go into the merits of the case.
- (viii). Some of the user-bodies have pleaded that, in the alternative, this Authority may arbitrate in the matter. This is not possible since, for arbitration, both the parties have to consent; and, equally importantly, this Authority is an adjudicative and not an arbitral body.

9. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides that it is not legally appropriate for it to intervene in the matter at this stage. That being so, the representation of the Chennai Steamer Agents' Association is rejected.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt/III/IV/143/2000/Exty.]